छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

Cr.M.P. नं. 2444/2019

देवेंद्र चंद्र, पुत्र बलराम चंद्र, लगभग 21 वर्ष की आयु, आर/ग्राम किकिरदा, P.S. बिर्रा, जिला। जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

--- आवेदक (जेल में)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य स्टेशन हाउस अधिकारी,

पुलिस स्टेशन हसौद, जिला जांजगीर–चांपा,

--- अनावेदक

आवेदक के अधिवक्ताः श्री रवींद्र शर्मा, अधिवक्ताः

अनावेदक/राज्य के अधिवक्ताः श्री रवि भगत, उप सरकारी अधिवक्ता और

श्रीमती आस्था शुक्ला, पैनल वकील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर आदेश

15/11/2019

1. इस आपराधिक विविध याचिका में शामिल संक्षिप्त प्रश्न निम्नलिखित राज्यों पर विचार करने के लिएः –

> "क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति जिसके विरुद्ध क्षेत्राधिकार पुलिस, हालांकि के तहत आरोप पत्र दायर किया है दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2)। निर्धारित अवधि के भीतर गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों का लेकिन आपूर्ति नहीं की है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 207 के तहत दिए गए आरोप पत्र की प्रति। उक्त अवधि के भीतर, हकदार होगा उपधारा (2) के परंतुक (क) के अधीन व्यतिक्रम जमानत देने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167"?

2. उपरोक्त प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में उत्पन्न होता हैः –

2.1 अभियुक्त/आवेदक को अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। धारा 489 ए, 489 बी, 489 सी, 489 डी, 255, 256 और 20/06/2019 को भारतीय दंड संहिता (इसके बाद, "आईपीसी") की धारा 120–बी और जाँच पूरी

हो गई और उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया क्षेत्राधिकार आपराधिक न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकार पुलिस पर उनकी गिरफ्तारी का 89 वां दिन i.e. 17/09/2019 को, लेकिन पुलिस ने नहीं किया आरोप–पत्र की प्रति उसे (अभियुक्त) [एक के भीतर] प्रदान करें 90 दिनों की अवधि] दण्ड प्रक्रिया संहिताकी धारा 207 के तहत विचार किया गया और अंततः उनकी गिरफ्तारी के 95 वें दिन उन्हें इसकी आपूर्ति की गई i.e. 23/09/2019 को अपने वकील के माध्यम से।

2.2. उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण एक आवेदन दाखिल किया गया की उपधारा (2) के परन्तुक (क) के अधीन अभियुक्त/आवेदक द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167। अन्य बातों के साथ यह कहते हुए कि यद्यपि आरोप – शीट 17/09/2019 को दायर की गई है, लेकिन उसी दिन, वह था न्यायिक आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और प्रतिलिपि उसके बाद 95 वें दिन उसे आरोप पत्र की आपूर्ति की गई गिरफ्तारी i.e. 23/09/2019 को, इसलिए, उपरोक्त के आधार पर प्रावधान, वह डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.3 सीखा हुआ परीक्षण मजिस्ट्रेट ने दायर उक्त आवेदन को खारिज कर दिया अभियुक्त/आवेदक को दिनांक 23/09/2019 के आदेश के अनुसार कोई योग्यता नहीं मिली और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए उक्त आदेश को रिहा करने से इनकार कर दिया डिफ़ॉल्ट जमानत पर अभियुक्त/आवेदक, चुनौती दिए जाने पर, था पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 05/10/2019 के आदेश द्वारा पुष्टि की गई जो के तहत इस आपराधिक विविध याचिका दायर करने की आवश्यकता दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482। उसके (अभियुक्त) तक विस्तार करने के लिए डिफ़ॉल्ट खंड के तहत जमानत का विशेषाधिकार।

3. श्री रवीन्द्र शर्मा, अभियुक्त/आवेदक के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि हालांकि आरोप पत्र के भीतर दायर किया गया था गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों की वैधानिक अवधि अभियुक्त/आवेदक लेकिन आरोप पत्र की प्रति नहीं थी उसे (अभियुक्त को) 90 दिनों के भीतर आपूर्ति की गई और न ही उसे दाखिल करने की तारीख को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया आरोप पत्र, और न ही आरोप पत्र की प्रति की आपूर्ति की गई थी आरोप–पत्र दाखिल करने की तारीख को, जैसा कि इसके अधीन विचार किया गया है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207। और अंत में, प्रति की आपूर्ति की गई थी 95 वें

दिन i.e. पर 23/09/2019 अपने वकील के माध्यम से, इसलिए, अभियुक्त/आवेदक के अधीन जमानत पर रिहा होने का हकदार है ऊपर उल्लिखित डिफ़ॉल्ट प्रावधान। वह आगे इस पर भरोसा रखता है ***दोधा बनाम राज्य में मध्य प्रदेश*** उच्च न्यायालय का निर्णय M.P.[1]

4. श्री रवि भगत और श्रीमती आस्था शुक्ला, विद्वान राज्य वकील प्रस्तुत करेंगे कि आरोप पत्र दाखिल करने के लिए वैधानिक अधिदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत। उस चरण की परिकल्पना करता है जब संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच पूरी नहीं हुई है निर्धारित अवधि। इस मामले में, जांच की गई है 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया गया गिरफ्तारी और अभियुक्त/आवेदक पर भी आरोप पत्र दायर किया गया है 89 वां दिन i.e. 17/09/2019 को, लेकिन आरोप पत्र की प्रति 95 वें दिन यानी i.e पर उनके वकील के माध्यम से उन्हें आपूर्ति की गई थी। पर 23/09/2019 Cr.P.C की धारा 207 के तहत। और अनुपलब्धता आरोप–पत्र की प्रति और कुछ नहीं बल्कि केवल एक अनियमितता है। इसके अलावा, एक बार निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, धारा के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत या वैधानिक जमानत देने का सवाल दण्ड प्रक्रिया संहिता के 167 (2)। उत्पन्न नहीं होता है, जैसे, याचिकाकर्ता नहीं है जमानत पर रिहा होने का हकदार है और याचिका योग्य है बर्खास्त कर दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षों के लिए विद्वान परामर्श सुना है, उन्हें उनका प्रतिद्वंद्वी माना जाता है प्रस्तुतियाँ और अधिकतम के साथ रिकॉर्ड के माध्यम से चला गया निरीक्षण।

6. यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है कि आरोपी एक अक्षम्य कार्य करता है। उपधारा (2) के परंतुक (क) के अधीन जमानत में प्रवेश पाने का अधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167। यदि मामले की जांच नहीं की जाती है 60 या 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया गया, मामला हो सकता है

1 1992 (II) MPWN 125

और आरोप पत्र उपरोक्त के भीतर दायर नहीं किया गया है – बताई गई अवधि। [देखें: ***हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य। v. की स्थिति महाराष्ट्र और ओआरएस***.[2] ; ***उदय मोहनलाल आचार्य बनाम राज्य महाराष्ट्र***[3] ***और अंत में, राकेश कुमार पॉल बनाम राज्य असम***[4]]

7. तत्काल मामले में, हालांकि आरोप पत्र 90 के भीतर दायर किया गया था अभियुक्त/आवेदक की गिरफ्तारी की तारीख से दिन, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत विचार किया गया। लेकिन प्रतिलिपि अभियुक्त/आवेदक को 95 तारीख को आरोप पत्र की आपूर्ति की गई थी उनकी गिरफ्तारी के दिन, इस प्रकार, सवाल यह उठता है कि क्या 90 दिनों की अवधि के बाद आरोप –पत्र की आपूर्ति का अधिकार होगा उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) वह जल्द से जल्द प्रदान करें जैसे ही जाँच पूरी होती है, पुलिस का प्रभारी अधिकारी स्टेशन लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को भेजेगा पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान, प्रपत्र में एक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित। एक बार ऐसी रिपोर्ट है दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट के खंड (बी) के तहत अपराध का संज्ञान लेता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1)। और उसके बाद में आगे बढ़ने के लिए अध्याय XV। में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामला दण्ड प्रक्रिया संहिता इससे पहले की कार्यवाही शुरू करने से संबंधित मेजिस्ट्रेट"

9. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207। अभियुक्त को आपूर्ति प्रदान करता है पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति , जिसमें कहा गया है

2 (1994) 4 SCC 602
3 (2001) 5 SCC 453
4 (2017) 15 SCC 67

के अंतर्गतः – "सेक. 207. अभियुक्त को पुलिस की प्रति की आपूर्ति रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज। जहां किसी भी मामले में एक पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू की गई है , मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के अभियुक्त को प्रस्तुत करेगा , निः शुल्क, निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति –

i. पुलिस रिपोर्ट;

ii. धारा के अधीन अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट 154;

iii. की उपधारा (3) के अधीन अभिलिखित कथन उन सभी व्यक्तियों की धारा 161, जिनके विरुद्ध अभियोजन इसके गवाहों के रूप में जाँच करने का प्रस्ताव करता है, इसके अलावा उसके संबंध में किसी भी भाग से जिसके लिए ऐसा अनुरोध किया गया है के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया है धारा 173 की उपधारा (6);

iv. अभिलिखित स्वीकारोक्ति और कथन, यदि कोई हों, धारा 164 के तहत;

v. कोई अन्य दस्तावेज या उसका प्रासंगिक उद्धरण पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया धारा 173(5)दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्तगंत।

बशर्ते कि मजिस्ट्रेट , अवलोकन के बाद कथन का ऐसा कोई भाग जिसे खंड में निर्दिष्ट किया गया है (iii) और पुलिस द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करना। अनुरोध के लिए अधिकारी, उस हिस्से की उस प्रति को निर्देशित करें मजिस्ट्रेट के रूप में बयान या उसके ऐसे हिस्से का उचित समझता है, अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाएगाः

बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि खंड (v) में निर्दिष्ट कोई भी दस्तावेज है भारी मात्रा में, वह अभियुक्त को प्रस्तुत करने के बजाय उसकी एक प्रति के साथ, निर्देश दें कि उसे केवल अनुमति दी जाएगी व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर के माध्यम से इसका निरीक्षण करें Court."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 238 निम्नानुसार प्रदान करता हैः – "सेक. 238. धारा 207 का अनुपालन–कब, पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित कोई वारंट मामला, अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होता है या लाया जाता है मुकदमा शुरू होने पर, मजिस्ट्रेट स्वयं को संतुष्ट करें कि उसने प्रावधानों का पालन किया है धारा 207 "

11. उच्चतम न्यायालय, तरुण त्यागी बनाम केन्द्रीय[5] के मामले में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अनुपालन की आवश्यकता पर जोर दिया दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 देय राशि देकर निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्त को अपना बचाव करने का अवसर और रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 के तहतः –

"8. धारा 207 अभियोजन पक्ष पर एक दायित्व डालती है – अभियुक्त को, निः शुल्क, प्रतियां प्रदान करें उसमें उल्लिखित दस्तावेज , बिना किसी देरी कि यह. दस्तावेज़ या उनके प्रासंगिक उद्धरण शामिल हैं जिन्हें पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है संहिता की धारा 173 (5) के अधीन उसका प्रतिवेदन। इस तरह की अनुपालन पहली तारीख को किया जाना है जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होता है या लाया जाता है। धारा के रूप में मुकदमे की शुरुआत संहिता की धारा 238 मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करने का आदेश देती है स्वयं कि धारा 207 के प्रावधान किए गए हैं अनुपालन किया। धारा 207 के प्रावधान में कहा गया है कि यदि–

दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के बजाय विशाल हैं अभियुक्त को उसकी प्रति के साथ, मजिस्ट्रेट अनुमति दे सकता है अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या उसके माध्यम से इसका निरीक्षण करना है अदालत में वकील "।

12. अब, विचार के लिए आगे का सवाल यह होगा कि क्या प्रावधान है दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत। अनिवार्य है और क्या इसका गैर–अनुपालन घातक है और इसका कारण बनेगा अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5 (2017) 4 SCC 490

13. दंड प्रक्रिया की नई संहिता, 1973 की धारा 207 यह निरसित संहिता की धारा 173 (4) और (5) के अनुरूप है। निरस्त संहिता के तहत, यह अधिकारी का वैधानिक कर्तव्य था निर्दिष्ट प्रतियों की आपूर्ति करने के लिए पुलिस स्टेशन का प्रभार अभियुक्तों को दस्तावेज। क्योंकि पुलिस अधिकारी ने नहीं किया उस कार्य का संतोषजनक ढंग से और बिना किसी विलम्ब के निर्वहन करना उसका कर्तव्य है अब मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेते हुए स्थानांतरित कर दिया गया है अभियुक्त को पठनीय और उचित प्रतियों की आपूर्ति सुनिश्चित करें वर्तमान खंड के तहत।

14. नारायण राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[6] के मामले में पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (4)। माना हैकि के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए एक पुलिस अधिकारी द्वारा चूकदण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 को इस तरह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए मुकदमे सहित कार्यवाही को प्रस्तुत करने के रूप में दूरगामी प्रभाव 6 एआईआर 1957 एससी 737 (वी. 44) सत्र न्यायालय के समक्ष, पूरी तरह से अप्रभावी। का अनुच्छेद 10 निर्णय, यहाँ प्रासंगिक होने के कारण, नीचे निकाला गया हैः –

> "10... क्या इस तरह की चूक आवश्यक रूप से सम्पूर्ण कार्यवाहियां और विचारण शून्य और शून्य हैं ; या के संदर्भ में केवल एक अनियमित इलाज योग्य संहिता की धारा 537 (क) के उपबंध? दूसरे शब्दों में , धारा 207 क (3) के साथ पठित धारा 173 (4) के उपबंध हैं अनिवार्य या केवल निर्देशिका ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन प्रावधानों को लागू किया गया है को सरल बनाने के लिए 1955 के अधिनियम का संशोधन तक के लिए अग्रणी पूछताछ के संबंध में प्रक्रिया सत्र परीक्षण , और एक ही समय में सुरक्षा के लिए पुलिस को आदेश देकर अभियुक्त व्यक्तियों के हित संबंधित अधिकारी और मजिस्ट्रेट, जिनके समक्ष इस प्रकार कार्यवाही लाई जाती है, यह देखने के लिए कि सभी दस्तावेज ,

6 AIR 1957 SC 737 (V. 44)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त व्यक्तियों को सभी देने के लिए आवश्यक
उनके बचाव के उचित संचालन के लिए जानकारी, हैं
सुसज्जित।
इसकी ओर से उचित रूप से तर्क दिया गया है
अपीलार्थी कि यह देखना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य था
कि संहिता के उपरोक्त प्रावधान किए गए हैं
पूरी तरह से अनुपालन। इसलिए, मजिस्ट्रेटों को होना चाहिए
इस तरह की कार्यवाही का संचालन करते समय, देखने के लिए
ताकि अभियुक्त व्यक्ति विकलांग न हों
पुलिस अधिकारियों की ओर से किसी भी चूक से बचाव
संबंधित, आवश्यक प्रतियों की आपूर्ति करने के लिए।
लेकिन हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि
उन प्रावधानों का अनुपालन , अनिवार्य रूप से ,
उन कार्यवाहियों को दूषित करने का परिणाम और बाद में
मुकदमा। "शॉल" शब्द दोनों उप –अनुभागों (4) में आता है।
धारा 207 क की 173 और उपधारा (3) अनिवार्य नहीं है परन्तु केवल
निर्देशिका, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक चूक , को
धारा 173 के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया जाना चाहिए
2019 को प्रस्तुत करने के लिए इस तरह के दूरगामी प्रभाव की अनुमति
न्यायालय के समक्ष विचारण सहित कार्यवाहियां सत्र पूरी तरह से अप्रभावी... "।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उच्चतम न्यायालय, ***उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में बनाम . लक्ष्मी ब्राह्मण और Anr.***[7], वैधानिक दायित्व माना जाता है धारा 207 के साथ पठित धारा के अधीन मजिस्ट्रेट पर अधिरोपित दण्ड प्रक्रिया संहिता का धारा 209 दस्तावेजों की प्रतियां निःशुल्क प्रस्तुत करना और अभिनिर्धारित किया कि यह एक न्यायिक दायित्व और मजिस्ट्रेट का कार्य है धारा 207 के तहत एक परीक्षण नहीं है, लेकिन एक परीक्षण के अलावा कुछ और है और न्यायिक कार्य होने के कारण यह अनिवार्य रूप से एक जांच होगी। रिपोर्ट के पैराग्राफ 12 और 13 नीचे उद्धृत किए गए हैंः –

"12... धारा 207, जो उस समय थी, ने इसे अनिवार्य बना दिया था –
मजिस्ट्रेट को मुफ्त में, प्रतियों की आपूर्ति करने के लिए
अनुभाग में दिए गए दस्तावेज। उस पर लगाया गया कर्तव्य

7 (1983) 2 SCC 372

मजिस्ट्रेट द्वारा एस। 207 को न्यायिक में निष्पादित किया जाना था
तरीके से। सेक का पालन करने के लिए। 207 जो एक में डाली जाती है
अनिवार्य भाषा , जब अभियुक्त को पेश किया जाता है
मजिस्ट्रेट के सामने, उसे पूछताछ करनी होती है
अभियुक्त अपना बयान दर्ज करके कि क्या प्रतियाँ
सेक में निर्धारित विभिन्न दस्तावेजों का। 207 हो चुके हैं।
उसे दिया या नहीं। कोई वचनबद्ध आदेश नहीं
सत्र न्यायालय में अभियुक्त को इसके तहत बनाया जा सकता है
सेक. 209 जब तक मजिस्ट्रेट पूरी तरह से अनुपालन नहीं करता है
सेक के प्रावधान। 207. और अगर यह दिखाया जाता है कि प्रतियां
प्रासंगिक दस्तावेजों या उनमें से कुछ नहीं हैं
दी गई, मामले को प्राप्त करने के लिए स्थगित करना होगा
प्रतियाँ तैयार की गईं और अभियुक्त को दी गईं। यह है।
धारा 207 और एस में निहित। 209 पर प्रदान करता है कि
संतुष्ट किया जा रहा है कि आवश्यक प्रतियां किया गया है
अभियुक्त को आपूर्ति की गई , मजिस्ट्रेट आगे बढ़ सकता है
अभियुक्त को खड़े होने के लिए सेशन कोर्ट में भेजें
उसका मुकदमा। सेक द्वारा अधिरोपित वैधानिक दायित्व। 207
सेक के साथ पढ़ें। 209 मजिस्ट्रेट पर मुफ्त में प्रस्तुत करने के लिए
7 (1983) 2 एससीसी 3722019: सीजीएचसीः 30720
तटस्थ उद्धरण दस्तावेजों की प्रतियों की लागत एक न्यायिक दायित्व है।
यह है प्रशासनिक कार्य नहीं। यह एक न्यायिक कार्य है
जिसे न्यायिक तरीके से निष्पादित किया जाना है। यह है।
स्पष्ट रूप से संभव है कि प्रतियाँ तैयार न हों।
इससे कुछ लोगों के लिए मामले को स्थगित करना आवश्यक हो जाता है वह
समय जो प्रतियाँ तैयार करने में खर्च किया जाता है और
अभियुक्त को वही प्रदान करना। मजिस्ट्रेट कर सकते हैं
अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ें
न्यायिक रूप से कार्य का निर्वहन करने के बाद ही सत्र
सेक द्वारा उस पर थोपा गया। 207. यह निष्कर्ष है
अध्याय XVIII में निहित प्रावधानों द्वारा दृढ़
जिसने किसी मामले के विचारण के लिए प्रक्रिया निर्धारित की
सत्र न्यायालय। सेक . 226 खोलने के लिए प्रदान करता है
अभियोजन के लिए मामला। सेक. 227 बिजली प्रदान करता है
अभियुक्त को आरोपमुक्त करने के लिए सत्र न्यायालय यदि
मामले के अभिलेख पर विचार करना और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, न्यायाधीश विचार करता है कि इसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है अभियुक्त को। सत्र न्यायालय पर कोई कर्तव्य नहीं डाला जाता है मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ने से पहले पूछताछ करना सेक के तहत अभियोजन। 226 यह पता लगाने के लिए कि क्या दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं अभियुक्त क्योंकि धारा 207 पर दायित्व डालता है न्यायिक कार्य करने के लिए मजिस्ट्रेट।

13. अब, अगर सेक के तहत। 207, मजिस्ट्रेट प्रदर्शन कर रहा है यह पता लगाने का एक न्यायिक कार्य कि क्या प्रतियां हैं आपूर्ति की गई या नहीं , यह निस्संदेह एक जांच होगी स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से वह सेक। 207 है। अक्षर और भावना में अनुपालन किया गया। वह संतुष्टि न्यायिक संतुष्टि होनी चाहिए। यह एक परीक्षण नहीं है लेकिन एक परीक्षण और न्यायिक कार्य होने के अलावा कुछ और यह अनिवार्य रूप से एक जांच होगी। एक आदेश बनाना अभियुक्त को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना समान रूप से जाँच और जाँच में एक चरण हो प्रतिबद्धता का क्रम बनाने में समाप्त होता है। इस प्रकार , अभियुक्त के पेश होने या पेश किए जाने के समय से पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष सेक। 170 और मजिस्ट्रेट पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ता है कि क्या सेक. 207 का अनुपालन किया गया है और फिर आगे बढ़ता है अभियुक्त को सत्र न्यायालय को सौंपें , मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही एक जाँच होगी जैसा कि सेक द्वारा विचार किया गया है। कोड के 2 (जी) हम इसे पाते हैं। उच्च न्यायालय से सहमत होना मुश्किल है कि कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा सेक के अधीन आरोपमुक्त किया गया। 207 है। एक न्यायिक कार्य के अलावा कुछ और जबकि कार्य का निर्वहन मजिस्ट्रेट एक आयोजित नहीं कर रहा है संहिता द्वारा विचार के अनुसार जांच... "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपर्युक्त के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटना स्थापित कानूनी स्थिति, यह काफी स्पष्ट है कि जांच एक पर आती है जिस क्षण पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, उस क्षण को समाप्त करें

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के साथ धारा 170 पढ़ें। और मजिस्ट्रेट निम्नलिखित प्रतियों की आपूर्ति में न्यायिक कार्य करता है दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207, और आरोपी को जारी नहीं किया जा सकता है दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत। उस जमीन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत प्रतियां। उसे नहीं दिया गया 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर , इस प्रकार, उपचार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत मजिस्ट्रेट का कार्य। भाग के रूप में जांच और इस तरह, मुकदमे द्वारा आरोप पत्र की आपूर्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत आवेदन के लिए मजिस्ट्रेट के साथ तीन दिनों की देरी परंतुक के अर्थ में नहीं आएगी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) (a) के लिए। और अभियुक्त/आवेदक उस आधार पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपरोक्त दृष्टिकोण में , मेरे निर्णय द्वारा समर्थित हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बनाम कांति ग्रोवर [8]. मामले के उस दृष्टिकोण में, निर्णय इस पर निर्भर था अभियुक्त/आवेदक के लिए विद्वान वकील द्वारा i.e. दोधा (ऊपर) है काफी अलग है और दोनों अदालतों में पूरी तरह से उचित हैं आवेदक द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करना।

18. उपर्युक्त चर्चा के परिणाम के रूप में, यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध याचिका। गुणों से रहित होना, होने के योग्य है और तदनुसार है खारिज कर दिया। कोई व्यय नहीं।

हस्ता/–

संजय के. अग्रवाल

न्यायाधीश

---

8 2004 Cr.L.J 4355

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur